



पेज 05 में...
परीक्षा सुधारों पर PM
मोदी का बड़ा एलान

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 27 जुलाई से 02 अगस्त 2026

हम दिखाएंगे आईना...



पेज 06 में...
मीराबाई चानू ने
जीता गोल्ड मेडल

वर्ष : 02 अंक : 21 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपये

www.shaharsatta.com



पेज

04

खुरचन- जब जनता हँसने लगे, तो सावधान हो जाइए...!

जनता के द्वार डिजिटल सरकार

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

लोकतंत्र की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शासन की नीतियां और सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितनी सहजता से पहुंचती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे भौगोलिक विविधताओं वाले राज्य में, जहां घने जंगल, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी अंचल शामिल हैं, आम जनता तक सरकारी दफ्तरों की पहुंच बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती को आधुनिक तकनीक से मात देते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने *सेवा सेतु* पोर्टल की शुरुआत की है। यह मंच केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि 'संवाद से सशक्तिकरण' का एक ऐसा माध्यम है जिसने सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गतिशीलता लाकर जनसेवा को नए मायने दिए हैं।

सेवा सेतु

डिजिटल सुशासन
की नई पहचान

अब 520
शासकीय सेवाएं
घर बैठे एक
क्लिक पर



उल्लेखनीय उपलब्धियां

36 विभागों की सेवाएं
एक ही डिजिटल मंच पर

520+
शासकीय सेवाएं
ऑनलाइन उपलब्ध

39 लाख+
आवेदन प्राप्त

95.9%
आवेदनों का
सफल निराकरण

16,700+
सेवा केंद्र नागरिकों की
सुविधा के लिए संचालित

समय, श्रम
और धन की बचत

पारदर्शिता और
जवाबदेही सुनिश्चित

घर बैठे आसान
और सुरक्षित सेवाएं



रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में "सेवा सेतु" पोर्टल एक प्रभावी और अभिनव डिजिटल माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करते हुए सेवा सेतु के माध्यम से अब नागरिकों को अधिकांश शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट से सेवा सेतु तक का सफर:

पूर्व में राज्य में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को केवल 86 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का विस्तार कर इसे "सेवा सेतु" के रूप में विकसित किया गया। आज यह पोर्टल 36 विभागों की 520 से अधिक शासकीय सेवाओं का एकीकृत डिजिटल मंच बन चुका है, जहां विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा आवेदन, ट्रैकिंग और सेवा प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।

घर बैठे एक क्लिक में 520 शासकीय सेवाएं:

इस सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे ही विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल से समय, श्रम और धन की बचत होने के साथ-साथ सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है।

ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार:

सेवा सेतु को केवल एक ऑनलाइन पोर्टल तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसकी पहुंच प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके प्रभावी संचालन हेतु पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों तथा संबंधित विभागीय कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार करना है। पंचायत स्तर पर सेवा सेतु केंद्रों को जनसुविधा का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी डिजिटल सेवाओं का समान लाभ मिल सके।

सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध श्रेणीवार 520 प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं

- व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्यिक सेवाएं -106
- लाइसेंस, परमिट एवं विनियामक सेवाएं - 85
- सामाजिक कल्याण, पेंशन एवं वित्तीय सहायता सेवाएं -65
- शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक सेवाएं - 58
- भूमि, संपत्ति एवं राजस्व सेवाएं - 37
- व्यक्तिगत पहचान एवं प्रमाण पत्र सेवाएं - 35
- शासकीय अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति सेवाएं 31
- जन शिकायत, सुरक्षा एवं विधिक सेवाएं- 25
- रोजगार, कौशल एवं श्रम सेवाएं- 19
- केंद्र सरकार की सेवा-19
- भुगतान, कर एवं वित्तीय लेनदेन सेवाएं-18
- कृषि, ग्रामीण एवं आजीविका सेवाएं-15
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं-7

नकटी मुद्दे पर कांग्रेस का एक्शन प्लान राज्यपाल को फिर लिखेगी चिट्ठी

कानूनी लड़ाई के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई



रायपुर। नवा रायपुर के नकटी गांव में तोड़फोड़ और विस्थापन के मामले में कांग्रेस ने अपना अगला कदम तय कर लिया है। नकटी मामले में गठित की कांग्रेस कमिटी की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। पार्टी ने राज्यपाल को दोबारा अनुरोध पत्र भेजने, पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाने और प्रभावित परिवारों को उसी जगह मकान देने की मांग दोहराई है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना को करीब एक महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक प्रभावित परिवारों के लिए कोई ठोस फैसला नहीं ले सकी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित कलेक्टर से लेकर राज्यपाल और सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं।

लड़ने के लिए कांग्रेस के विधि विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जो पूरे मामले के कानूनी पहलुओं पर काम करेगी। पार्टी ने यह भी मांग की है कि जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें उसी स्थान पर दोबारा मकान बनाकर दिए जाएं। इसके अलावा कांग्रेस ने नकटी में तोड़फोड़ वाली जगह और आसपास की जमीनों की राजस्व ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। बैज ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को पता चल सकेगा कि उस इलाके में किन प्रभावशाली लोगों की जमीन है और किनके दबाव में गरीबों के घरों पर कार्रवाई की गई।

प्रभावितों के साथ पहले भी मिले चुके हैं राज्यपाल से

लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सरकार अब भी मौन है। बारिश के बीच प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बैज ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहले भी प्रभावितों के साथ राज्यपाल से मिला था। उस दौरान राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का भरसा दिया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।

बैठक में लिए गए चार फैसले

कांग्रेस समिति की बैठक में तय किया गया कि पार्टी नकटी मामले के समाधान के लिए राज्यपाल को फिर से अनुरोध पत्र भेजेगी। प्रभावित परिवारों की ओर से कानूनी लड़ाई

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर रायपुर में जश्रः बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी

रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रायपुर में छात्र-युवाओं ने खुशी जताते हुए जश्र मनाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। युवाओं ने कहा कि देशभर के छात्रों, सामाजिक संगठनों और शांतिपूर्ण आंदोलनों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह किसी व्यक्ति की हार या जीत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले करोड़ों छात्रों और युवाओं की जीत है।

उनका कहना था कि लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग उठाई जा रही थी। युवाओं ने कहा कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष का पहला बड़ा परिणाम है। हालांकि उनका मानना है कि केवल नेतृत्व परिवर्तन से

काम नहीं चलेगा। अब केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने और शिक्षा सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। रायपुर में हाल ही में सोमन वांगचुक के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान एनएसयूआई के पांच कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों ने खून से 'धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दो' लिखकर विरोध दर्ज कराया था। आंदोलन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल इस्तीफा नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार कराना है। उनका कहना है कि सरकार को पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कानून बनाना चाहिए।



कारोबारी को चाकू दिखाकर मारने की धमकी

रायपुर। उधारी के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में कारोबारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी विवाद करता नजर आ रहा है। पीड़ित की पहचान मोहम्मद समीर खान और आरोपी की पहचान सोहेल खान के रूप में हुई है। कारोबारी ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। समीर खान का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाकर केवल मारपीट के मामले में कार्रवाई की और मुचलके पर छोड़ दिया। उनका कहना है कि आरोपी अब भी हथियार लेकर घूम रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का मामला है। पीड़ित मोहम्मद समीर खान नवापारा इलाके का रहने वाला है और बकरी खरीद-बिक्री का काम करता है। शिकायत के अनुसार, 24 जुलाई की सुबह करीब 9:45 बजे उधारी के पैसे मांगने को लेकर उसका आरोपी सोहेल खान से विवाद हो गया।

रायपुर में सराफा कारोबारी से 2 लाख की ठगी

रायपुर। टिकरापारा क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी से करीब 2 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने पहले सोना खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान किया। इसके बाद दूसरा ऑर्डर रद्द कराकर कारोबारी से उसकी राशि वापस ले ली। कुछ दिन बाद कारोबारी को बैंक खाते में जमा रकम होल्ड होने की जानकारी मिली, तब ठगी का पता चला। इस मामले में कुल 1,99,440 रुपए की राशि होल्ड हो गई, जिससे कारोबारी को नुकसान हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



शिकायत के अनुसार, संजय नगर निवासी अजय सोनी की टिकरापारा मेन रोड पर अजय ज्वेलर्स नाम से दुकान है। 17 जुलाई को एक युवक स्कूटी से दुकान पहुंचा। उसने 6 ग्राम सोना खरीदने की बात कही। दुकान में 5 ग्राम का सोने का सिक्का उपलब्ध था, जिसकी कीमत 76,220 रुपए थी। युवक ने

JAGDAMBA TC के नाम से ऑनलाइन भुगतान किया। इसके बाद उसने 1,600 ग्राम सोना और खरीदा, जिसकी कीमत 23,500 रुपए थी। इसका भी ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उसने करीब एक घंटे बाद सोना लेने की बात कहकर दुकान से चला गया। कुछ देर बाद लौटकर युवक ने दूसरा ऑर्डर रद्द करने और उसकी रकम वापस करने की मांग की। इस पर कारोबारी ने उसके मोबाइल नंबर पर 23,500 रुपए

ऑनलाइन वापस कर दिए। 20 जुलाई को कारोबारी अजय सोनी के पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को JAGDAMBA TC का प्रतिनिधि बताया और कहा कि उसके खाते में 3.50 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसके बाद अजय ने अपना बैंक खाता चेक किया। खाते में 78,757 रुपए दिखाई दे रहे थे, लेकिन करीब तीन घंटे बाद बैलेंस माइनस 20,962 रुपए हो गया।

कारगिल विजय दिवस पर रायपुर में निकली साइकिल रैली



रायपुर। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शनिवार सुबह रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में 100 से ज्यादा साइकिलिस्ट शामिल हुए। सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और बच्चों ने एक साथ साइकिल चलाकर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रैली का आयोजन मुख्यालय मध्य भारत एरिया के तहत छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया ने नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA), टूर डी रायपुर साइक्लिंग ग्रुप और आईटीएसए हॉस्पिटल के सहयोग से किया। रैली सुबह रायपुर से शुरू हुई और नवा रायपुर के सेंद्र लेक पहुंचकर समाप्त हुई। पूरे रास्ते प्रतिभागियों ने देशभक्ति का संदेश दिया और कारगिल के वीर जवानों के बलिदान को याद किया।

रैली में सेना के जवानों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का मकसद कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देना और नई पीढ़ी को उनके साहस और बलिदान से परिचित कराना था। रैली के दौरान



आईटीएसए हॉस्पिटल की टीम मेडिकल सहायता के लिए मौजूद रही। वहीं, एनआरडीए ने ट्रैफिक और पूरे रूट की व्यवस्था सभाली ताकि आयोजन बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।

ब्रिगेडियर टी.एस. बावा ने किया सम्मानित

समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर टी.एस. बावा ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की। उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके साहस और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की गाथा से जोड़ते हैं। कार्यक्रम के अंत में रैली में शामिल साइकिलिस्टों को सम्मानित भी किया गया।

रायपुर में अब कहीं भी पोस्टर फ्लेक्स लगाने पर लगेगा जुर्माना

रायपुर। अब बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर लगाने पर जुर्माना लगेगा। रायपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों पर ई-चालान के जरिए जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने शहर के सभी 10 जनों में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए अलग-अलग स्थान तय किए हैं। इन जगहों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत की जाएगी।

नगर निगम ने दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान वे अपनी दुकानों पर लगे अनधिकृत ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री हटा सकते हैं या नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं। निगम ने साफ किया है कि बिना अनुमति दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही लिखा जा सकता है। किसी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का प्रचार करने वाले बोर्ड या विज्ञापन लगाने के लिए निगम की अनुमति जरूरी होगी। एक सप्ताह बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निगम ने हर जोन में अलग-अलग स्थान चिह्नित किए हैं।



रायपुर में AI गणपति मूर्तियां बनाने से बच रहे मूर्तिकार

रायपुर। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। रायपुर में भी बप्पा के स्वागत की तैयारियां जारी हैं। शहर के मोहल्लों, चौक-चौराहों और घरों में करीब 15 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मूर्तिकार दिन-रात प्रतिमाओं को रूप देने का काम कर रहे हैं। इस बार भगवान गणेश के शिव, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बाल गणेश, बालाजी और अर्धनारीश्वर जैसे कई स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हालांकि, एक बात सबसे अलग है। इस बार अधिकांश मूर्तिकार AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार डिजाइन वाली प्रतिमाएं बनाने से बच रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले साल रायपुर के लाखे नगर में एक गणेश प्रतिमा के स्वरूप को लेकर विवाद हुआ था। हिंदू संगठनों ने प्रतिमा के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी। मामला इतना बढ़ गया कि विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस तक शिकायत पहुंची। इस घटना के बाद अधिकांश मूर्तिकारों ने तय किया कि धार्मिक प्रतिमाओं में AI जैसे प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे किसी तरह का विवाद खड़ा न हो। मूर्तिकार यशवंत ने बताया कि AI से बनी तस्वीरें आकर्षक लगती हैं, लेकिन पूजा के लिए प्रतिमा बनाने समय धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हम ऐसे डिजाइन नहीं बनाते, जिन पर बाद में विवाद की आशंका हो।

12वीं पास ने पैसे डबल करने का झांसा देकर ठग लिए 500 करोड़

रायपुर। छह महीने में पैसे डबल करने के झांसे में मानपुर के आम लोगों के साथ-साथ नेता और सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी आ गए। इनका जाल बालाघाट के लॉजी, गोदिया से लेकर चंद्रपुर और मानपुर तक फैला। कुछ ही सालों में करीब 500 करोड़ रुपए लोगों से



ठगे गए। हाल ही में बालाघाट पुलिस ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि एक एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है, जिसमें रिमोड पर लिए गए आरोपियों से 18.61 करोड़ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 14.82 करोड़ के 617 चेक और 122 जमीनों की रजिस्ट्री बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि जब्त रजिस्ट्रियों के आधार पर सभी निवेशकों की सुनवाई कर उन्हें राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 20 जुलाई को पुलिस ने चार साल से फरार मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने समेत उसके सात साथियों तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायने, दिनेश कंकरायने, रामप्रसाद मंसूरे, प्रद्युम्न कंकरायने और रूखचंद हरदे को गिरफ्तार किया। इन पर 63 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सभी से पूछताछ जारी है। एसआईटी प्रमुख एवं सीएसपी मयंक तिवारी के अनुसार मुख्य आरोपियों प्रद्युम्न कंकरायने, रामप्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकरायने के ठिकानों से 122 जमीनों की रजिस्ट्रियां मिली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 18.61 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 20 रजिस्टर, भूमि ऋण पुस्तिका, पावर ऑफ अटॉर्नी, लगभग 1500 कोरे चेक, 59 बैंक इंस्टा किट, टैक्स और जीएसटी रिटर्न से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि जब्त रजिस्ट्रियों में दर्ज सभी निवेशकों की पहचान कर उनकी सुनवाई की जाएगी, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी रकम वापस दिलाई जा सके। इस संबंध में जल्द ही पुलिस विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा।



इनमें बूढ़ातालाहा का पुराना धरना स्थल, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, कबीर चौक प्लाईओवर की दीवार, आईएसबीटी की बाउंड्री वॉल, गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी, पानी टंकियों के परिसर और जून कार्यालयों की बाउंड्री वॉल समेत कई स्थान शामिल हैं।

घाट के दोनों किनारों पर पहुंचे परिवारों ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। कई लोग अपने साथ घर से भोजन बनाकर लाए थे, जबकि कुछ ने मौके पर ही भोजन तैयार किया। पेड़ों की छांव में बैठकर परिवारों ने समय बिताया और बच्चों ने खुले वातावरण में खेलकूद का आनंद लिया। ठकुराइन टोला घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और बेहतर सुविधाओं के कारण धीरे-धीरे राज्यपुरवासियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंच रहे हैं।



संपादकीय

• सुकांत राजपूत



CJP आंदोलन के बड़े हासिल और सबक

नीट पेपर लीक प्रकरण, परीक्षा प्रणालियों में सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर 'काँकरोच जनता पार्टी' (CJP) का 36 दिनों से चला आ रहा जंतर-मंतर का आंदोलन अंततः समाप्त हो गया है। एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान से शुरू होकर सड़कों तक पहुँचे इस छात्र संग्राम ने न केवल सरकार को झुकाया, बल्कि भारतीय छात्र राजनीति और नागरिक विरोध के इतिहास में एक नया अध्याय भी लिखा है। अब जब धुआँ छँट चुका है, तो बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम और व्यापक विरोध प्रदर्शन का ज़मीनी हासिल क्या रहा?

इस प्रदर्शन का सबसे तात्कालिक और प्रत्यक्ष परिणाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा रहा। हाल के वर्षों में यह दुर्लभ देखने को मिला है जब किसी बड़े जनआंदोलन या छात्र विरोध के दबाव में किसी केंद्रीय मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा हो। इसने यह संदेश साफ कर दिया कि लाख-लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था में हुई धांधली को सरकार अब महज 'तकनीकी खराबी' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। विरोध प्रदर्शनों के अक्सर हिंसक होने या लंबा खींचने पर सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों व युवाओं का होता है, जिन पर पुलिस केस दर्ज हो जाते हैं।

CJP और सरकार के बीच हुई लिखित वार्ता में दिल्ली सहित अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज 15 से 20 FIRs को वापस लेने तथा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने की गारंटी मिली है। युवाओं के करियर को कानूनी पचड़ों से बचाना इस वार्ता की एक बड़ी रणनीतिक जीत है। CJP द्वारा प्रस्तुत पाँच-सूत्रीय सुधार ज्ञापन को लेकर केंद्र सरकार (गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर) ने लिखित में गहन समीक्षा और चरणबद्ध क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है। इससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह आंदोलन दिखाता है कि भारत में जन-विरोध का स्वरूप बदल रहा है। किसी मुख्यधारा के राजनीतिक दल के पारंपरिक ढांचे के बिना, सिर्फ AI टूल्स, मीम्स और सोशल मीडिया की ताकत से शुरू हुआ आंदोलन जब सोनम वांगचुक जैसे विचारकों और आम छात्रों की ज़मीनी भागीदारी से जुड़ा, तो इसने संसद तक की नींद उड़ा दी।

हालाँकि, इस हासिल के साथ कुछ गंभीर सबक भी जुड़े हैं। जंतर-मंतर पर हुई झड़पें, लाठीचार्ज, और आंदोलन का कुछ हद तक राजनीतिक दलों की होड़ का केंद्र बन जाना यह याद दिलाता है कि जन-आंदोलनों को अहिंसक और उद्देश्य-केंद्रित बनाए रखना कितना कठिन होता है। कुल मिलाकर, 'काँकरोच जनता पार्टी' के इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि जब युवाओं और छात्रों की आवाज़ में एकजुटता हो, तो व्यवस्था को जवाबदेह बनना ही पड़ता है। सरकार के लिए हासिल यह है कि उसने समय रहते संवाद का रास्ता चुनकर स्थिति को और बेकाबू होने से बचा लिया, और छात्रों के लिए हासिल यह है कि अब 'पेपर लीक' जैसे मुद्दों पर लीपापोती करना किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा।

अपनी समस्याओं को दूर भगाएं



एक आदमी का प्यारा गधा एक गहरी खाई में गिर जाता है। वह लाख कोशिश करने के बावजूद उसे बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए वह उसे जिंदा दफनाने का फैसला करता है। गधे पर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। गधा बोझ महसूस करता है, उसे झाड़ता है और उस पर पैर रखता है। फिर और मिट्टी डाली जाती है। वह बोझ झाड़कर ऊपर चढ़ गया। जितना अधिक भार उस पर डाला गया, वह उतना ही ऊपर उठता गया। दोपहर तक गधा हरी-भरी घास के मैदानों में चर रहा था। समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पाने

और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने के बाद, व्यक्ति हरी-भरी चरागाहों में चरने लगेगा।

जब जनता हँसने लगे, तो सावधान हो जाइए...!

कभी-कभी लोकतंत्र में जनता इतनी परेशान हो जाती है कि उसके पास रोने के लिए आँसू भी नहीं बचते। तब वह हँसती है और जब उसकी हँसी में व्यवस्था की मूँछें ऐंठने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि व्यंग्य पैदा हो चुका है। व्यंग्य से असंतोष के तड़के के साथ युवा शक्ति जुड़ जाती है तो फिर वह केवल साहित्य नहीं रह जाता, व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान का रूप ले लेता है।

व्यंग्य को अक्सर हल्का समझा जाता है। कहा जाता है— “अरे, व्यंग्य है।” लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार व्यंग्य ही सबसे गंभीर बात होती है। काँकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। एक तंज भरी टिप्पणी से उपजा यह नाम, हताश और बेरोजगार युवाओं के बीच प्रतिरोध की पहचान बन गया। जिस शब्द को अपमान के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी को युवाओं ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहचान में बदलने का प्रयास किया। यह अपने आप में व्यंग्य की ताकत का प्रमाण है। विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों और मीडिया घरानों ने इस आंदोलन को अभूतपूर्व और व्यंग्यात्मक राजनीतिक विद्रोह बताया।

बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से उपजे युवा आक्रोश ने बता दिया है कि जनता की हँसी को हल्के में लेना सत्ता की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज का युवा पढ़ता है। डिग्री लेता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। कोचिंग जाता है। फॉर्म भरता है। फीस जमा करता है। परीक्षा देता है। फिर परिणाम का इंतजार करता है। कभी परिणाम नहीं आता तो कभी आता है और जब आता है तो विवाद आ जाता है। कभी विवाद खत्म होता है तो जाँच बैठ जाती है। और कभी जाँच बैठती है तो युवा सोचता है—अब शायद नौकरी मिलेगी। लेकिन तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। हमारे यहाँ बेरोजगार युवक को एक चीज मुफ्त में मिलती है—धैर्य रखने की सलाह।

सत्ता के लिए सबसे खतरनाक जनता वह नहीं होती जो गुस्से में चिल्ला रही हो। गुस्सा कभी-कभी थक जाता है। सबसे खतरनाक वह जनता होती है जो व्यवस्था की विसंगतियों पर हँसना शुरू कर देती है। क्योंकि तब डर खत्म होने लगता है और जिस दिन जनता सत्ता से डरना बंद कर देती है, लोकतंत्र उसी दिन थोड़ा मजबूत हो जाता है।

आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं माँग रहा। वह विश्वसनीय व्यवस्था माँग रहा है। वह चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष हो। वह चाहता है कि भर्ती समय पर हो। वह चाहता है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो। वह चाहता है कि उसकी मेहनत किसी अदृश्य व्यवस्था के आगे हार न जाए। अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तो यह आक्रोश धीरे-धीरे और गहरा होगा। और तब व्यंग्य भी और तीखा होगा। पहले व्यंग्य पोस्टर पर आएगा। इसके बाद नारे और मीम में और फिर आंदोलन के साथ अभूतपूर्व इतिहास बन जाएगा। इसलिए व्यंग्य को केवल मजाक समझना भूल

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास



होगी। व्यंग्य जनता की वह भाषा है जिसमें वह बिना भाषण दिए सत्ता से सवाल करती है।

वह कहती है—

“हम दुखी हैं, इसलिए हँस रहे हैं।

हम बेरोजगार हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं।

हम निराश हैं, इसलिए व्यंग्य कर रहे हैं।

और याद रखिए, हमारी हँसी को कमजोरी मत समझिए।”

क्योंकि जिस दिन जनता अपनी हँसी को हथियार बना लेती है, उस दिन सत्ता के सबसे मजबूत किले की दीवार पर भी एक दरार दिखाई देने लगती है। व्यंग्य की ताकत यही है। वह तलवार नहीं उठाता। वह सिर्फ मुस्कराता है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक पूरा सवाल छिपा होता है—

“हुजूर, सब ठीक है न?”

और सत्ता जितनी बार कहती है—“हाँ, सब ठीक है।” व्यंग्य उतनी ही जोर से पूछता है—

“तो फिर इतनी जाँच क्यों हो रही है?” बस, यहीं से सत्ता की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी और व्यंग्य की धार थोड़ी और सीधी हो जाती है।

जेन-जी में जिंदा है लोकतंत्र

अरुण कुमार त्रिपाठी

जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन महज एक विरोध नहीं, बल्कि डूबते लोकतंत्र के लिए एक नई उम्मीद है। पढ़िए, अरुण कुमार त्रिपाठी का विश्लेषण, कैसे भारत की युवा पीढ़ी ने तानाशाही और नफरती राजनीति को चुनौती दी है। अचानक पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने याद आने लगें। 1954 में ‘जागृति’ फिल्म आई थी। उसका एक गाना लोगों की जुबान पर लंबे समय तक चढ़ा रहा और आज भी पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कहीं न कहीं जरूर बजाया जाता है। रामचंद्र नारायण द्विवेदी उर्फ प्रदीप के लिखे और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए उस गीत के बोल कुछ इस तरह हैं:

हम लाए हैं तूफान से किशती निकाल के
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के
तुम ही भविष्य हो भारत विशाल के
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के
इसी तरह 1961 में ‘गंगा जमुना’ फिल्म आई। उसका भी शकील बदायूनी का लिखा हेमंत कुमार का गाना और स्कूल में फिल्माया जाने वाला गीत उतना ही लोकप्रिय हुआ। उसके बोल थे:

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के
यह देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के
दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना
सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के

यह दोनों गीत युवाओं के भीतर एक भारतीय नागरिक के दायित्वों का बोध पैदा करते हैं। उसे बेबी बूमर (62 से 68 वर्ष) वाली, जेन एक्स (46-61 वर्ष) वाली और मिलेनियल (30 से 45 वर्ष) वाली पीढ़ियों भूल गई थीं, नई पीढ़ी ने उसे फिर से याद दिला दिया है। जब संघ परिवार और उसकी सरकारों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को डूबोने के पूरे इंतजाम कर रखे हों तब भारत की युवा पीढ़ी ने जंतर-मंतर से शुरू करके पूरे देश में जो आंदोलन किया उसे महज ‘डूबते को तिनके का सहारा’ वाले मुहावरे से नवाजना अन्याय होगा। वह डूबती जम्हूरियत के लिए खंभा, जंजीर और नौका के सहारे के रूप में प्रकट हुआ है। अशोक के कलिंग विजय की तरह पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद मौजूदा सरकार ने अपने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रखा था उसे युवाओं ने पकड़ कर बांध लिया है। चीन के थियेनआनमन चौक की तरह अभिमान्यु के फिर से मारे जाने की भविष्यवाणी गलत निकली। इस बार अभिमान्यु जीत गया है और इंडिया अलायंस के पांडवों के परोक्ष समर्थन के बावजूद उनकी सीधी भागीदारी के बिना जीता है।

छात्रों की जीत

25 जुलाई को उसे जो जीत हासिल हुई है और उसे लेकर जिस तरह उत्साह का प्रदर्शन हुआ है उससे तानाशाही और नफरती इरादों के हौसले पस्त होते दिखे हैं। हालाँकि तानाशाहों के हौसले तो 25 जुलाई को ही पस्त हो गए थे। भले सत्ताधारियों ने करंट लोग डंडे, कील लगी लाठियाँ और पैलैट गनों से युवाओं का दमन किया लेकिन उसके बाद मधुमक्खियों की तरह से युवाओं और उनके समर्थकों ने सत्ताधारियों को घेर लिया। अचानक 12 वर्षों के अन्याय के विरुद्ध संचित आक्रोश फूट पड़ा।

इस पीढ़ी ने यह भी जता दिया कि उसे मंदिर-मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और प्राचीन भारत के गौरव के नाम पर लंबे समय तक बहकाया और बरगलाया नहीं जा सकता। उसे चैनलों और अखबारों के नफरती कार्यक्रम लंबे समय तक घृणा और हिंसा नहीं सिखा सकते। उसे अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए न कि आश्वासन और लंबे लंबे भाषण। उसकी निगाह में नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं और न ही राहुल गांधी पप्पू हैं। न ही कमजोर पड़ चुकी कम्युनिस्ट पार्टियाँ अर्बन नक्सली हैं। उसने सीपीआई और सीपीएम ही नहीं भूमिगत आंदोलन से निकली और लोकतांत्रिक मुख्याधारा में आ चुकी सीपीआई (एमएल) और उसके संगठन आइसा के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं पाला है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि काँकरोच जनता पार्टी नामक विलोम प्रहसन की छतरी के नीचे मार्क्सवादी दलों और आंबेडकरवादी दलों के विचारों का नवीकरण हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा शायद इसलिए भी हो पाया क्योंकि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों के भगवा एजेंड और विश्वविद्यालयों में संघ परिवार के शिक्षकों की नियुक्तियों के बावजूद यह पीढ़ी अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, ईरान की इस्लामी क्रांति, अफगान आजादी की लड़ाई और दुनिया में आजकल होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानती है। वह उस पर चर्चा करती है और आजादी उसे पसंद है। वह भगत सिंह और भीमराव आंबेडकर को पढ़ती है, संविधान सभा की बहसों को पढ़ती है और यह भी जानती है कि तानाशाही के सामने गांधी का तरीका कारगर है। इसलिए उनके असहयोग, सविनय अवज्ञा और अनशन के सत्याग्रही हथियारों का इस्तेमाल करती है। हालाँकि, संघ परिवार के विद्यालय और उनकी संस्थाओं ने सरकार पर शिक्षा को बदल डालने का जो दबाव बना रखा है उसे देखते हुए नहीं लगता कि इसके बाद



वाली पीढ़ी इतना खुलकर सोच पाएगी। क्योंकि जिस पीढ़ी ने यह आंदोलन किया उसने शायद एनसीईआरटी की वे किताबें पढ़ी थीं जिसका पूरी तरह भगवाकरण नहीं किया गया था।

युवाओं को यह जीत हासिल कैसे हुई?

पर असली सवाल यह है कि युवाओं को यह जीत हासिल कैसे हुई? चूंकि भारत में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, हालांकि उसमें कायरों की संख्या अधिक है। फिर भी भांति भांति के मतों के नाते यहां लोकतंत्र का एक भ्रम तो पैदा ही होता रहता है। वैसे तो भारत में ‘मुंडे मुंडे मतभिन्ना’ की स्थिति है लेकिन जिन दो मतों का यहां उल्लेख आवश्यक है उनमें एक है संघर्ष का सिद्धांत और दूसरा है साजिश का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों की अपनी अपनी तर्कप्रणाली है और उसके लिए उनके पास अपने अपने परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं।

संघर्ष के सिद्धांत वालों का कहना है कि युवाओं ने संघर्ष किया तो उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने अपने आंदोलन को अहिंसक रखा, उसमें तोड़फोड़ वाले तत्वों का प्रवेश नहीं होने दिया, आंदोलन पूरे देश में फैल गया और 20 जुलाई की सरकारों हिंसा के बावजूद उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे किसानों, मजदूरों और समाज की वरिष्ठ पीढ़ी और विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के भीतर उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ने लगा था। इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन को सोनम वांगचुक के 26 दिन तक चले आमरण अनशन से बल मिला और जब उनका अनशन समाप्त हुआ तब भी काकरोच जनता पार्टी ने तय किया कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यह भी लगा कि अगर सोनम वांगचुक की तरह सरकार के दबाव में काकरोचों ने आंदोलन वापस भी ले लिया तो भी दिल्ली के फुटपाथों पर सो रहे युवा उसे वापस नहीं लेंगे। लेकिन संघर्ष के सिद्धांत के समांतर साजिश का सिद्धांत भी काफी जोरशोर से उछाला गया है। संयोग से इस मायने में भाजपा और कांग्रेस के लोग एक ही जगह जाकर खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वगूरु और भगवान विष्णु का अवतार मानने वाले पहले भाजपाई तो आंदोलन को विदेशी शक्तियों द्वारा प्रेरित और सोनम वांगचुक को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे। और बार बार कह रहे थे कि विदेशी धन से चलने वाले आंदोलन के आगे धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि इस देश के तमाम लोगों को मोदी से राजनीति की दीक्षा लेनी चाहिए। देखो कैसे गुब्बारा फुलाकर उसकी हवा निकाल देते हैं। जैसे किसान आंदोलन की हवा निकाली, वैसे ही काकरोच आंदोलन को फुस्स कर दिया। कान थोड़ा घुमाकर पकड़ने वाले कांग्रेसी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। उ

नका कहना है कि लड़ाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोनम वांगचुक को तैयार किया अनशन करने के लिए। काँकरोच जनता पार्टी की भी सरकार से मिलीभगत थी। वे देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नीट के पेपरलीक से पैदा हुए आंदोलन को गरमा रहे थे और वह बढ़ रहा था। सरकार चाहती थी कि युवा राहुल के समर्थन में न उतरें और फिर उसे भटकाने और राहुल के नेतृत्व को छोटा करने के लिए सोनम वांगचुक को खड़ा कर दिया। सरकार को लगा था कि वे लोग थोड़े दिन अनशन करके चले जाएंगे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकलने लगा तो हस्तक्षेप करना पड़ा और धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इतिहास में साजिशें होती हैं। सरकारों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वे लीलाएं भी करती हैं। इसके बावजूद संघर्ष करने वाले लोग उनको दरकिनार करके अपने कर्म पर यकीन करते हैं। शायद गांधी ने यही किया। साजिश का सिद्धांत कुछ नियतिवाद के सिद्धांत जैसा लगता है। तुलसी दास ने एक जगह कहा है कि ‘उमा दारु जोशित की नाई। सबहिं नचावत राम गुसाईं’ यानी आप ‘होइहिं सोई जो राम रचि राखा, को करि कर्म बढावैं साखा।’ में यकीन कीजिए। अपने कर्म पर भरोसा मत कीजिए। यह मानिए कि कोई बड़ी शक्ति हम सब को नचा रही है। यह सिद्धांत एक तरह से आप को अकर्म्मण्य बनाता है। आइए सरकार की दैवीय शक्तियों में यकीन करना छोड़कर जनता की शक्ति और उसके संघर्ष के सिद्धांत में यकीन करें और मानें कि जेन-जी में लोकतंत्र जिंदा है।



114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील में आए तेज़ी

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की होने वाली डील को लेकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है. बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना की जरूरतों को देखते हुए इस साल मई महीने में फ्रांस को 114 राफेल फाइटर जेट्स की मेगा गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट डील के लिए एक लेटर ऑफ़ रिवेस्ट (LoR) जारी किया था, जिस पर अगस्त महीने के मध्य में फ्रांस का जवाब आने की उम्मीद जताई जा रही है. भारतीय रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि फ्रांस के अधिकारियों ने भारत की तरफ से मई महीने में फ्रांस को दिए लेटर ऑफ़ रिवेस्ट पर अपना अंतिम जवाब देने के लिए अगले महीने अगस्त के मध्य तक का समय मांगा है. उन्होंने बताया कि जब फ्रांस की तरफ से भारतीय LoR पर आधिकारिक रूप से जवाब आ जाएगा, तब इसके बाद दोनों पक्ष 114 राफेल फाइटर जेट्स की कीमत और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और फ्रांस के बीच होने वाली इस डील के तहत, फ्रांसीसी निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारत की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके भारत में ही 94 राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगी.

18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 12 घंटे के अंदर 18 राज्यों में भारी बारिश



आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जुलाई को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक कई राज्यों में मौसम बेहद खराब रह सकता है. कई इलाकों में 80 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और असम समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है.

भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती!

पश्चिमी ईरान में 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. यूरोपियन-मेडिटैरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार भूकंप का एपिसेंटर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था. रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र काहरिज शहर से लगभग 54 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था. काहरिज की आबादी करीब 7.66 लाख है. इसके अलावा भूकंप का केंद्र जावनरुद शहर से लगभग 33 किलोमीटर दक्षिण में भी स्थित था, जहां करीब 38,600 लोग रहते हैं. भूकंप के झटकों के बाद फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल के हताहत होने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है।

भारत पर 12.5 प्रतिशत लगने वाला था टैरिफ, फिर कम लगाया गया

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 17 देशों पर फोड़ा टैरिफ बम

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने फोर्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से जुड़े उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. अहम बात यह है कि ट्रंप ने भारत समेत 17 देशों के खिलाफ यह फैसला लिया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सेक्शन 301 के तहत यह निर्णय किया है. अमेरिका का नया टैरिफ शुक्रवार (24 जुलाई) से लागू हो जाएगा. यूएसटीआर की मानें तो ये कार्रवाई उन देशों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने फोर्ड लेबर से बने उत्पादों के आयात पर सख्त एक्शन नहीं लिया. अहम बात यह है कि ट्रंप ने भारत को निचले टैरिफ स्लैब में रखा है, जबकि कुछ देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया गया है. ट्रंप के आदेश के बाद 60 व्यापारिक साझेदार देशों की समीक्षा की गई थी.



क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (ट्रेड रिप्रजेंटेटिव) जेमिसन ग्रीर ने कहा कि यह कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को सुधारने की शुरुआत करेगा. वहीं ट्रंप ने कहा, 'मुझे व्यापार प्रतिनिधि ने सलाह दी है कि इन अर्थव्यवस्थाओं (देशों) के सामानों पर 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाना चाहिए, जिससे इन्हें ऐसे प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके.'

भारत-पाक समेत किन देशों पर लगा टैरिफ

अमेरिका ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, स्वाटेमाला, होंडुरस, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, निनिदाद एंड टोबैगो और ब्रिटेन पर भी 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. वहीं कई दूसरे देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

देश-विदेश

सोमवार, 27 जुलाई से 02 अगस्त 2026

05

परीक्षा सुधारों पर PM मोदी का बड़ा एलान

नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स



नई दिल्ली। निष्पक्ष-विश्वसनीय एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना तथा विद्यार्थियों का विश्वास बहाल करना अब केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जारी अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इसके लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। यह समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी और विशेष रूप से तकनीक आधारित सुधारों का खाका तैयार करेगी। साथ ही ऐसी व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश करेगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों का खतरा न्यूनतम हो सके। सरकार परीक्षा प्रणाली को और मजबूत कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी भी कर चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय

में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश करेंगे। सरकार का दावा है कि नए प्रविधानों से पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित नकल जैसे अपराधों पर और प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री इससे पहले भी दो वीडियो संदेश जारी कर आश्चस्त कर चुके हैं कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरे वीडियो में उनका जोर परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वे जेल में हैं। मामलों के तुरंत

निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन केवल दोषियों को सजा देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करने की है, जिस पर देश का हर छात्र बिना संदेह के भरोसा कर सके। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे।

एनटीए में प्रशासनिक बदलाव

प्रधानमंत्री की यह घोषणा हाल के प्रशासनिक फैसलों की अगली कड़ी मानी जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एनटीए में प्रशासनिक बदलाव कर चुकी है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रल्हाद जोशी को सौंपी गई है। अब परीक्षा सुधार के लिए देश के शीर्ष विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपना सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नंदन नीलेकणि का चयन इसी रणनीति के तहत किया गया है।

आंदोलन खत्म होने के बाद अब क्या करेगी CJP?

नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत सभी तीनों मांगे मानने के बाद कॉंकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है. वहीं अब सवाल ये है कि अब पार्टी का आगे का क्या प्लान है. इसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि अब हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे. सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "इस देश के युवा जाग गए हैं. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. उन्होंने सही चीज के लिए लड़ाई लड़ी है और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं. हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपने करीबी लोगों को खो दिया.

रांका ने आगे कहा, "हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य इन पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया है. और हमें सच में उम्मीद है कि



आज कुछ न्याय हुआ है. जो भी अगला शिक्षा मंत्री बने, हमें उम्मीद है कि वे ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपना काम करेंगे."

'पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे उठाएंगे'

आगे के प्लान के बारे में बात करते हुए आशुतोष ने कहा, "हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया था. इस देश के युवाओं के लिए, हम जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे." इससे पहले कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को सरकार के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद कॉंकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। वहीं, सीजेपी ने जंतर-मंतर से आंदोलन को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी मांग मान ली है और हम आंदोलन को खत्म करने का ऐलान करते हैं।

PoK में अब आर-पार की लड़ाई!

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में रविवार (26 जुलाई, 2026) ऐलान कर दिया गया है कि कल सोमवार (27 जुलाई, 2026) को किसी भी सूत्र में रावलकोट समेत पीओके के अन्य हिस्सों से जनता राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करेगी.

अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) की देर रात 2 बजे ये ऐलान किया कि पहले 15 जुलाई को मार्च होनी थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने उनके साथ 14 जुलाई से बातचीत शुरू की और उन्होंने 21 जुलाई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बाद भी न ही प्रदर्शनकारियों की एक भी मांग मानी गई और न ही प्रदर्शनकारियों और अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी घोषित करने का नोटिफिकेशन हटाया गया. ऐसे में कल 27 जुलाई को पूरे पीओके से मुजफ्फराबाद की ओर कूच का ऐलान किया गया है. अवामी एक्शन कमेटी का प्लान बताते हुए



सरदार उमर नजीर ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को आधी रात में घोषणा की थी कि रविवार (26 जुलाई) को पीओके के मीरपुर से काफिले रावलकोट में आकर इकट्ठा होंगे और फिर सोमवार (27 जुलाई) को साढ़े 12 बजे धुहर की नमाज के बाद रावलकोट और बाकी जगहों से काफिले सीधा मुजफ्फराबाद की ओर रवाना होंगे. विद्रोह के 47वें दिन प्लान के हिसाब से मीरपुर से रावलकोट की ओर विद्रोहियों

का सैलाब निकालना शुरू हो चुका है.

आरपार की लड़ाई का ऐलान करते हुए सरदार अमान खान, जो पीओके को पाकिस्तान से अलग करने की बात कई बार कर चुके हैं, ने मंच से ऐलान किया कि सोमवार (27 जुलाई, 2026) को जब मुजफ्फराबाद की ओर कूच होंगे, तो वो 38 मंग नहीं, सिर्फ दो मांग पर होंगी और वो पीओके की सत्ता पीओके के लोगों के हाथ में देना और पाकिस्तान की सरकार का हस्तक्षेप खत्म करना।

यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला

नई दिल्ली। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर रविवार (26 जुलाई) को 4 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ. कीव में भारतीय दूतावास के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चालक दल के 2 सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं, जबकि बाकी 2 के बारे में जानकारी का अभी भी इंतजार है. दूतावास के बयान के मुताबिक यह घटना शनिवार को हुई, जब ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN Ragnar पर हमला हुआ. ओडेसा यूक्रेन के अहम ब्लैक सी बंदरगाहों में से एक है, जिस पर 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से कई बार हमले हुए हैं. भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है. बता दें कि यह घटना ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है. यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि जहाज पर मौजूद दो भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, जबकि अन्य दो भारतीयों के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है तथा भारतीय नागरिकों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. घटना को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.



हार्दिक पांड्या के लिए 2 खिलाड़ी और 10 करोड़ देने को तैयार CSK

नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है. कुछ सप्ताह पहले CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने हार्दिक को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करने की खबरों को खारिज कर दिया था. अब हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चेन्नई सुपर किंग्स, हार्दिक को अपने स्ववाद में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे की मांग की थी. मुंबई टीम का मैनेजमेंट म्हात्रे को फ्यूचर टैलेंट के रूप में देखता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने 19 वर्षीय स्टार ओपनर को रिलीज करने को राजी नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स ने MI के सामने एक काउंटर ऑफर रखा है. सीएसके शिवम दुबे को रिलीज करने को तैयार है, लेकिन आयुष म्हात्रे की जगह उसने डेवाल्ड ब्रेविस को मुंबई भेजने का ऑफर दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं CSK की टीम हार्दिक पांड्या के लिए शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और साथ में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये देने को भी तैयार है. अगर दोनों फ्रेंचाइजी में इस बात पर सहमति बनी तो यह कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की डील होगी.



टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का किया क्लीन स्वीप

नई दिल्ली। भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. हरारे में खेले गए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए 81 रनों की बेहतरीन पारी खेली. गेंदबाजी में मयंक यादव ने फिर से कहर बरपाया और अशोक शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर का विकेट विकेट लिया. टी20 रैंकिंग में हाल ही में भारतीय टीम दोबारा से नंबर-1 बनी है. तीसरे मैच में जिम्बाब्वे पर 35 रनों की जीत से भारतीय खेमे की खुशी दोगुनी हो गई होगी. टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी, जिसने 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में 157 रन ही बना सकी. वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे. उनके ओपनिंग जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने प्लेयर्स होने की हैट्रिक लगाई, लेकिन वैभव ने 49 गेंद में 81 रनों की सधी हुई पारी खेली. अभिषेक सिर्फ 2 रन बना पाए. ईशान किशन ने 29 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों का योगदान दिया. रिंकू सिंह ने फिनिशर वाले अंदाज में 14 गेंद में 25 रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 192 तक पहुंचाया. जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई तो मयंक यादव ने सीरीज के पहले लेने की हैट्रिक पारी की पहली गेंद पर ब्रायन बैनेट को चलता किया. मयंक ने अपनी धारधार गेंदबाजी के बलबूते 3 विकेट चटकाए.

मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स में दमदार प्रदर्शन कर रचा इतिहास



नई दिल्ली। भारत की स्टार भारोत्तोलक (वेटलिफ्टर) और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने एक बार फिर पूरे देश का दिल जीत लिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया. उनके दमदार खेल की बदौलत भारत की झोली में गोल्ड मेडल आ गिरा है. इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने इन खेलों में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतकर अपनी गोल्डन हैट्रिक पूरी कर ली है. यानी लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रगान गूंजा है!

मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने 85 किलोग्राम का वजन उठाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. मीराबाई ने अपनी तीसरी कोशिश में बेहद आसानी से 85 किलोग्राम वजन उठा लिया और एक नया

पीएम मोदी ने दी बधाई

मीराबाई चानू ने लगातार चौथे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर इतिहास रचा है. वहीं पिछली तीन बार से उन्होंने वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई ने 48 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता. इस ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, "भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और नया अध्याय जुड़ गया. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर और इन खेलों का कुल चौथा मेडल जीतकर हर एक भारतीय को प्रेरित किया है. इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई और आगे की चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं."

मीराबाई चानू ने लगातार चार बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने की उपलब्धि हासिल की है. 2014 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद 2018, 2022 और अब 2026 कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने तीनों बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. रविवार को 48 किलोग्राम भारवर्ग में उन्होंने रनैच राउंड में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क राउंड में 105 किलो वजन उठाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने दोनों राउंड में अलग-अलग कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया.

मीराबाई चानू भारत की सबसे सफल वेटलिफ्टिस्टों में से एक हैं. 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर रही थीं. वो एक बार 48 किलोग्राम भारवर्ग में वेटलिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं.

ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बड़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट है. ऐसे में कई टैक्सपेयर्स और CAs ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के सिस्टम में परेशानी आने की शिकायत की है. बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर के कहा कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे उन्हें ITR फाइल करने और पैसा जमा करने में परेशानी हो रही है. यूजरस मुताबिक, कई लोगों को पोर्टल पर लॉग-इन करने में भी परेशानी हो रही है. कुछ लोगों का कहना था कि ये परेशानी कई घंटों तक हो रही थी, लेकिन कुछ यूजरस ने कहा कि पोर्टल बिल्कुल ही डाउन हो गया था, जिससे ITR फाइलिंग और पैसा जमा करने में भी परेशानी हो रही.

यूजरस क्या शिकायतें कर रहे हैं?

एक यूजर ने X पर लिखा, दो घंटे से इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है और ITR फाइल नहीं हो रही है और पैसा जमा भी नहीं हो रहा है. कम से कम इनकम टैक्स डे पर



तो पोर्टल सही से काम करना चाहिए था. वहीं, एक और यूजर ने लिखा कि ई-फाइलिंग पोर्टल काफी देर तक बंद रहा, इसी वजह से कोई भी रिटर्न फाइल या पैसा जमा नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी बताया कि अगर ये परेशानी जल्दी सही नहीं होती है तो 31 जुलाई की ITR फाइलिंग की लास्ट डेट आगे करनी चाहिए. लेकिन फिलहाल सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेडलाइन आगे करने को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है.

अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा ITR जमा किए गए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के हिसाब से इस साल 2026-27 के लिए अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा ITR जमा किए गए हैं. हर साल लास्ट डेट आने पर बड़ी तादाद में लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसे में पोर्टल पर अक्सर परेशानी भी आती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोर्टल में क्या परेशानी हुई हैं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा और ये भी नहीं बताया कि परेशानी क्यों हो रही थी।

गूगल पर 9800 करोड़ का जुर्माना लगते ही भड़के ट्रंप



अनुचित बताते हुए ट्रेड जांच शुरू करने और जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है. यूरोपीय आयोग ने गूगल पर डिजिटल मार्केट से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारी जुर्माना लगाया है. EU का कहना है कि गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म और सेवाओं का इस्तेमाल कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए किया. जुर्माने में गूगल पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने तथा ऐप डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धा को सीमित करने जैसे आरोप शामिल हैं. गूगल पर कार्रवाई के बाद ट्रंप ने यूरोपीय संघ के खिलाफ Section 301 जांच शुरू करने की बात कही है.

वाशिंगटन। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. यूरोपीय संघ ने गूगल पर करीब 9800 करोड़ रुपये यानी लगभग 1 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है. ट्रंप ने EU की कार्रवाई को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ

अगस्त से लॉन्च होगा CKYC 2.0

नई दिल्ली। CKYC 2.0 भारत के KYC सिस्टम का नया और आधुनिक संस्करण है. इसके जरिए आपको हर बैंक, बीमा कंपनी या वित्तीय संस्था में बार-बार आधार, पैन या एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी. एक बार KYC पूरा होने के बाद आपकी मंजूरी से वही रिकॉर्ड अलग-अलग संस्थानों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे बैंकिंग सेवाएं पहले से अधिक आसान और तेज हो जाएंगी.

रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के बैंक और बीमा कंपनियां अगस्त से CKYC 2.0 शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. इस नई व्यवस्था में ग्राहक की अनुमति मिलने के बाद बैंक और बीमा कंपनियां केंद्रीय डेटाबेस से उसकी पहले से सत्यापित KYC जानकारी देख सकेंगी. इस साल के अंत तक म्यूचुअल फंड कंपनियां और स्टॉक ब्रोर्स भी इससे जुड़ सकते हैं. इससे लोगों को बार-बार लिए दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे, नया खाता या निवेश शुरू करने की प्रक्रिया तेज होगी और बैंकिंग व अन्य सेवाओं का लाभ लेना पहले से अधिक आसान हो जाएगा.



CKYC 2.0 क्या है?

CKYC 2.0 भारते के KYC सिस्टम का नया ओर बेहतर संस्करण है. इसके लागू होने के बाद आपको हर बैंक, बीमे कंपनी या दूसरे संस्थानो में बार-बार आधार, पैन या एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका KYC हो चुका है, तो OTP के जरिए मंजूरी मिलने पर संबंधित संस्था केंद्रीय KYC रिकॉर्ड के जरिए आपकी जानकारी ले सकेगी. यानी हर बार नया खाता खुलवाने, बीमा खरीदने या KYC अपडेट कराने के लिए वही दस्तावेज दोबारा जमा नहीं करने पड़ेंगे. इससे KYC की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, आसान और झंझट-मुक्त हो जाएगी. CKYC 2.0 की शुरुआत सबसे पहले अगस्त से बैंकों और बीमा कंपनियों में की जाएगी, ताकि ग्राहकों की KYC प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और आसान हो सके. इसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनियां, स्टॉक ब्रोर्स और अन्य पूंजी बाजार से जुड़े संस्थान भी चरणबद्ध तरीके से इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे.

स्मार्ट टिप्स अपनाकर बचाएं अपने पैसे

रात में ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

नई दिल्ली। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. अब लोगों को कपड़ों से लेकर ग्रांसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के समान के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब लोग मिनटों में घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग दिनभर बिजी रहने के कारण देर रात आराम से मोबाइल पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यही आदत जरूरत से ज्यादा खर्च का कारण बन जाती है. दरअसल, रात के समय लोग आराम के मूड में होते हैं और बिना ज्यादा सोच-समझ के ऑफर या डिस्काउंट देखकर ऑर्डर कर लेते हैं. ऐसे में कई ऐसे प्रोडक्ट भी कार्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिनकी जरूरत हमें नहीं होती है.

रात में क्यों बढ़ जाता है फिजूल खर्च?

रात के समय लोगों का नौद ज्यादा रिलैक्स होता है और ऐसे में लोग ज्यादातर सोशल मीडिया या शॉपिंग ऐप स्कॉल करते हुए कई ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जिनकी वास्तव में उन्हें कोई जरूरत नहीं होती. इस दौरान लिमिटेड टाइम ऑफर, पलैश सेल और भारी डिस्काउंट जैसे मैसेज देखकर अचानक जल्दबाजी में खरीदारी करने का मन बन जाता है. इस आदत को इम्पल्स बायिंग कहा जाता है, जो धीरे-धीरे आपकी बजट को बिगाड़ सकती है.



ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें?

- खरीदारी से पहले जरूरी सामान की लिस्ट तैयार करें.
- सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट देखकर सामान न खरीदें.
- महंगी चीज खरीदने से पहले सोचें कि उसकी हमें सच में जरूरत है या नहीं.
- फ्री डिलीवरी या कैशबैक के लालच में गैर-जरूरी सामान खरीदने से बचें.
- हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग का बजट तय करें.
- समय-समय पर अपने ऑनलाइन खर्च की नियमित समीक्षा करें.
- खरीदने से पहले कीमत जरूर करें चेक

अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी सामान को खरीदने से पहले अलग-अलग वेबसाइट और ऐप पर उसकी कीमत को ध्यान से देखें. अगर आपको उस सामान की तुरंत जरूरत नहीं है, तो एक-दो दिन इंतजार करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कई बार कुछ समय बाद वही प्रोडक्ट कम कीमत में बिकने लगती है.

Layoffs के बाद IT सेक्टर की तस्वीर बदली

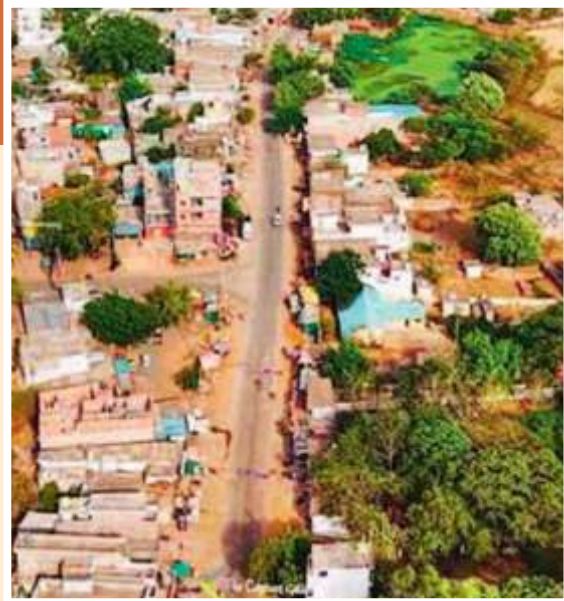
सिओला। पिछले दो सालों में भारतीय आईटी सेक्टर ने तेज बदलाव देखा है. महामारी के बाद जबरदस्त भर्ती करने वाली कंपनियां अब AI, ऑटोमेशन और कमजोर वैश्विक मांग के कारण लागत घटाने पर जोर दे रही हैं. इसी वजह से FY26 में कई बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या कम की, जबकि नई भर्ती की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. FY26 में भारत की पांच बड़ी IT कंपनियों यानी टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा का कुल कर्मचारी काउंट घटा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों में करीब 7,000 कर्मचारियों की टोटल कमी दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष FY25 में इन्होंने कंपनियों ने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नेट भर्ती की थी. सबसे बड़ा असर टीसीएस में देखने को मिला, जहां वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग की गई. छंटनी के बावजूद कंपनियों ने पूरी तरह सैलरी बढ़ाना बंद नही किया है, लेकिन पहले की तुलना में अप्रैजल काफी कम हो गया है. जैसे टीसीएस के प्रदर्शन आधारित सैलरी हाइक पर जोर दिया है. Infosys भी चुनिंदा कर्मचारियों का परफॉर्मेंस के बेसिस पर वेतन बढ़ा रही है. AI और डिजिटल स्किल्स वाले कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं. वहीं, HCLTech स्किल-बेस्ड रिवाइर्स और क्रिटिकल टैलेंट रिटेंशन पर फोकस कर रही है।

छत्तीसगढ़ के छत्तीस गढ़ों में पामगढ़

डा. टी. आर. रामटेके

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 40 कि मी दूरी पर बिलासपुर - शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर पामगढ़ जांजगीर जिला मुख्यालय से 21 कि मी दूरी पर स्थित है। पामगढ़ उत्तरी अक्षांश 21°-40' तथा पूर्वी देशांतर 82°-30' पर स्थित है। पामगढ़ के मुरुम मिट्टी से निर्मित बाहरी परकोटा की परिधि लगभग 1400 मीटर है। भूतल पर परकोटे की चौड़ाई 50 मी व ऊंचाई 10 मी है।

इस प्रकार के बाहर की ओर वृत्ताकार खाई है, जिसकी परिधि 450 मी तथा भूतल पर चौड़ाई 25 मी व ऊंचाई 7 मी है। बाहरी खाई के भीतर पामगढ़ का व्यास लगभग 300 मी है। जनश्रुति के अनुसार पामगढ़ के केंद्रीय स्थल से बाहर की ओर 2 कि मी लंबी एक गुप्त सुरंग थी तथा गढ़ की पूर्व दिशा में सिंह द्वार था, जिसके कोई भी अवशेष वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। गढ़ के भीतर पेयजल हेतु एक कुआ भी था।



अंग्रेजों के सामने न झुके न टूटे-गुंडाधूर

सुधीर सक्सेना

भूमकाल प्रसंग का महत्वपूर्ण ग्राम उलनार जगदलपुर तहसील के अंतर्गत पूर्वी बस्तर का एक ग्राम है। यहां 'भतरी' बोली जाती है। उलनार में ही हथियार इकट्ठे किए गए। क्रांति की शपथ ली गई और यहीं से माड़िया धुरवा क्रांतिकारी भत्ता बांध कर, लाल मिर्च बंधी आम की टहनियां लेकर प्रचार हेतु निकल पड़ते थे।

डारा मिर्च देखकर अन्य वनवासी भी भूमकाल में सम्मिलित हुए। गुंडाधूर धुर आदिवासी था। बस्तर ही उसकी दुनिया थी। स्कूल कभी गया नहीं। जीवन में शायद ही कभी केशकाल घाटी के नीचे उतरा हो। बावजूद इन सबके उसका

चरित्र खांटी सात्विक है। अपने समय के वीरों में आपकी नीति बिल्कुल ही अलग रही।

उन्होंने न तो हथियार डाले, न अंग्रेजों के हाथ लगे, और न ही समर्पण किए। गुंडाधूर एक महानायक हैं क्योंकि वह अविचारित शक्तियों का भंडार है, जो आदिम परिवेश में एक महानायक के लिए अपरिहार्य हैं। गुंडाधूर और लाल साहब में प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों गजामुंग मितान और सिरहा थे। जगदलपुर में मूरतसिंह बख्शी की हवेली में अक्सर बैठके हुआ करती थीं। गुंडाधूर की क्रांति प्रतिभा यहीं सक्रिय हुई।



सुंदर विचार वाले लोगों का गांव है सुंदरा



पवन यादव 'पहुना'

जननी और जन्मभूमि मनुष्य के लिए कभी भुला देने वाली स्थान नहीं होता। गांव का नाम सुंदरा पड़ा, इस पर गंभीरता से गांव के बुजुर्गों व बुद्धिजीवियों से चर्चा करने पर कई कारण गांव के नाम के पीछे कारण बताते हैं। जिसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस गांव में पहले कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, गांव के लोग मिल जुलकर रहते थे तथा गांव के किसी समस्या आने पर बिना भेदभाव के निपटा लेते थे। कोई कचहरी को तो न देखे न जानते थे। आसपास के गांव के लोग सुंदरा गांव की तारीफ किया करते थे। सभी सुंदर विचार वाले लोगों का गांव होने के कारण गांव का नाम रखा गया सुंदरा।

गांव राजनांदगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। गांव में बहुत पुराना रामायण समिति है जो 1946 में गठित हुआ है। प्राथमिक पाठशाला का निर्माण 1956 में हुआ है जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल माननीय डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के कर कमलों द्वारा किया गया। अजय नाथ बाबा का आश्रम, माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। गांव से लगा हुआ प्रसिद्ध कबीर आश्रम है। गांव में सड़क किनारे प्रसिद्ध दंत चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय है।

भूकंप के कारण नष्ट होने का अनुमान सिरपुर के सुरंग टीला मंदिर



ललित शर्मा

देखने में आता है कि भूकंप आने पर बड़े बड़े नगर और राजधानी कुछ पलों में धरती में समा जाती हैं। धरती का एक बार थरथराना ही हजारों लाखों लोगों को काल के आगोश में समा देने के लिए काफी होता है। श्रीपुर के पतन में भूकंप की भूमिका भी रही होगी। भूकंप के चिन्ह सुरंग टीला स्थित पंचायत मंदिर के अधिष्ठान अधिष्ठान में दिखाई देती है। देखा जाए तो सुरंग टीला मंदिर की जगती भारत के मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 43 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसका तल विन्यास नदी के तल से 17 फुट ऊंचा है। वर्तमान में मंदिर की सीढ़ियां दबी हुई हैं। इनके कोण बदले हुए हैं। विशाल मंदिर की संरचना में परिवर्तन सिर्फ भूकंप से ही आ सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रीपुर या सिरपुर में भूकंप भी आया होगा, जिसके कारण यह नगर ढह गया होगा।

विकास की दशा और दिशा बदली राजा साहब शिव मंगल सिंह ने



डॉ रामचंद्र सिंहदेव

सन 1900 में राजा साहब शिवमंगल सिंह ने अपनी राजधानी को सोनहत से बैकुंठपुर में स्थानांतरित कर दिया। बैकुंठपुर लगभग कोरिया रियासत के केंद्र बिंदु में था। इस कारण वहां से समस्त राज्य का प्रशासन बेहतर ढंग से किया जा सकता था। उन्होंने दो तालाब एवं एक मंदिर का निर्माण कराया जो नए महल के निकट स्थित है। इनके परिवार की बहन बाई देव कुंवर में मनुष्यों की प्रकृति को पहचानने की अद्भुत प्रतिभा थी। इसके साथ साथ वे ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने के साथ ही कूट राजनीतिज्ञ भी थी। राजा साहब ने उन्हें तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी के समस्त अधिकार प्रदान किए। वे प्रशासनिक कार्यों में राजा साहब की सहायता करती थी। वे अत्यंत धार्मिक एवं दानशील स्वभाव की महिला थी, जो सदैव गरीबों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सहायता किया करती थी। समाज के लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उन्हें स्नेहपूर्वक बाई साहब कह कर सम्बोधित किया जाता था। बैकुंठपुर में बाई साहब के नाम से एक तालाब खुदवा कर उसका नाम बाई सागर रखा गया। सन 1906 में उनका स्वर्गवास हो गया।

पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में विच्छेदन होने को कहा जाता है : छाड़रा छाड़ी

एम. एस. पैकरा

छत्तीसगढ़ अंचल में छाड़रा छाड़ी शब्द जशपुर - सरगुजा की स्थानीय बोली के आधार पर कहा जाता है। जब पति और पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने पर दोनों में विचारों में मतभेद के कारण, पति अथवा पत्नी द्वारा एक दूसरे को प्रताड़ित करने के कारण दोनों के बीच सम्बन्ध टूट जाता है, और पत्नी अपने पति से अलग होकर अपने मायके चली जाती है। ऐसे समस्या को सामाजिक नियमानुसार हल किया जाता है। यदि सामाजिक व्यवस्था में कोई निर्णय को मानते नहीं तो दंड लेकर अलग रहने के लिए मान्य किया जाता है जिसे छाड़रा छाड़ी कहा जाता है। इस निर्णय के बाद पत्नी को अपने पूर्व पति के संपत्ति में हक पाने का अधिकार नहीं रहता। आगे दोनों पति पत्नी अब अपने अनुसार दूसरी कर सकते हैं।



सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार



डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुई त्वरित, पारदर्शी और आसान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

520

शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं



95.9%

आवेदनों का निराकरण



38 लाख+
आवेदन



16,700+
सेवा केंद्र



36 विभाग
एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ जाति प्रमाण पत्र
- ✓ आय प्रमाण पत्र
- ✓ निवास प्रमाण पत्र
- ✓ विवाह प्रमाण पत्र
- ✓ राशन कार्ड सेवाएं
- ✓ पेंशन योजनाएं
- ✓ नाम परिवर्तन सेवा
- ✓ व्यापार लाइसेंस



अधिक
जानकारी हेतु
← स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400